

संक्षिप्त

शिक्षा विभाग में धूल खा रहे प्रस्ताव

गोंदिया : जिले में शिक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है। यहां अनेक शिक्षकों की कमी है वहीं जर्जर इमारतें शिक्षा क्षेत्र में अभिशाप बनकर सामने आ रही हैं। जिला परिषद की अधिकतर डिजिटल शालाओं में भौतिक व शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। डिजिटल शालाएं केवल कागजों पर डिजिटल बन कर रह गई हैं। जिसमें सुविधाएं व व्यवस्थाओं के हाल बेहाल हैं। इमारतें अति जर्जर अवस्था में हैं वहीं शौचालय की सुविधा तक उपलब्ध नहीं हैं।

फत्तेपुर में वंचित की कार्यकारिणी घोषित

गोंदिया : वंचित बहुजन आघाड़ी, तहसील गोंदिया (ग्रामीण) की कार्यकारिणी का पुनर्गठन फत्तेपुर स्थित समाज भवन में आयोजित बैठक में किया गया। शुरुआत तथागत गौतम बुद्ध व डा. बाबासाहेब आंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर पंचशील व बुद्ध पूजा के साथ की गई बैठक में संगठन के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रचार-प्रसार को लेकर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि संगठन के मार्गदर्शक एड. प्रकाश उर्फ बालासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व और मार्गदर्शन में समाज के वंचित व उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से गोंदिया तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में नरेंद्र बोकर (बिरसी) को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष पद पर अनिल डोंगरे, कैलाश वसंत देशभ्रतार व रामप्रसाद देशभ्रतार को नियुक्त किया गया। वासुदेव तुकाराम कठाणे को महासचिव, सेवकदास मुकाजी मेश्राम को सहसचिव, उत्तम रामटेके को कोषाध्यक्ष तथा हेमराज चंद्रकापूरे को संचटक नियुक्त किया गया। मनोहर उदारामजी बडगे को सलाहकार बनाया गया। कार्यकारिणी में झनकलाल डोंगरे, नैमलाल सावनकर, फत्तीराम डोंगरे, राजेश डोंगरे, दिलीप खोब्रागड़े व घनश्याम डोंगरे को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आभार उत्तम रामटेके ने माना।

35 हजार रु. के आभूषण उड़ाए



गोंदिया: ग्रामीण थाने के तहत मरारटोली निवासी फियादी भीमराज भरताराम कुंभरे (49) के घर के दरवाजे का अज्ञात व्यक्ति ने ताला तोड़कर अलमारी में रखे 35 हजार रु. कीमत के सोने के आभूषण चुरा लिया। फियादी की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

गोंदिया पुलिस की धड़ाकेबाज कार्रवाई

कत्ल के लिए ले जाए जा रहे ४२ गोवंशीय पशु जब्त

13 लोगों पर मामला दर्ज

संवाददाता / गोंदिया
सालेकसा पुलिस थाने की सीमा में कत्ल के लिए गोवंशीय पशुओं की निर्दयता से और अवैध रूप से दुलाई करने वाले गिरोह का स्थानीय अपराध शाखा ने पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो कंटेनर ट्रकों से 42 गोवंशीय पशुओं को छुड़ाया है और पशुओं सहित दो कंटेनर और मोबाइल ऐसा कुल 51 लाख 87 हजार रुपये का माल जब्त किया है। इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जिले में अवैध धंधों पर कार्रवाई करने के लिए स्थानीय अपराध शाखा की टीम गश्त पर थी, तभी दलदलकूही परिसर से दो कंटेनर ट्रकों में गोवंशीय

पशुओं को कत्ल के लिए ले जाए जाने की पुख्ता गोपनीय जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर टीम ने दलदलकूही से धनेगांव मार्ग पर नाकाबंदी की। संदिग्ध दोनों कंटेनरों को रोककर जांच करने पर, एक कंटेनर में 25 और दूसरे कंटेनर में 17, इस तरह कुल 42 गोवंशीय पशुओं को बेहद ठूस-ठूसकर और क्रूरता से बांधकर रखे जाने का पता चला। पूछताछ के दौरान, सैफर भाई ने इन पशुओं को दलदलकूही परिसर से खरीदकर कलमना (नागपुर) के मुंजबिल कुरैशी और फैजल हसन के पास भेजे जाने की बात सामने आई। पशुओं की अवैध दुलाई को सुगम बनाने के लिए कंटेनर मालिक जावेद अहमद व हरीलाल ब्रिजभानसिंग ने वाहन में



विशेष बदलाव करवाए थे।

इस मामले में कंटेनर चालक इंदिरा कुरैशी (उम्र 50, नागपुर), अन्वर शब्बीर अली (उम्र 46, कामठी), लेबर अब्दुल रहमान असलम (उम्र 38), फैजल अन्सारी, रोहीत डेहरे (उम्र 25), गुलाम रसूल (उम्र 40), रिताबाई मोहबे और उसके पति सहित

संबंधित 13 आरोपियों के खिलाफ सालेकसा पुलिस थाने में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे के निर्देशानुसार व स्थानीय अपराध

शाखा के पुलिस निरीक्षक रेवचंद सिंगनजुडे के मार्गदर्शन में सपोनि अभिषेक जंगमवार, पोहवा तुलसीदास लुटे, राजकुमार खोटेले, दुर्गेश तिवारी, प्रकाश गायधने, पोशि सुनील डहाके, हंसराज भांडारकर, चालक पोशि निलेश ठाकरे और राम खंदारे ने की।

काउंटर से 72,000 नकद किए चोरी

संवाददाता / गोंदिया
शहर थाने के तहत सिंधी कॉलोनी निवासी फियादी रुपकुमार प्रभुदास बजाज (56) के कपड़ा लाईन स्थित बजाज फैंसी क्लॉथ स्टोर रेडीमेट साड़ी दुकान के पीछे के खिड़की की लोहे की ग्रील तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने अंदर एवं सांसद जैन का आभार व्यक्त किया। ट्रेन के स्वागत अवसर पर देवेंद्रनाथ चौबे और अन्य नागरिक एवं यात्री उपस्थित थे।

शालाओं में नहीं लगे अग्निरोधी यंत्र

संवाददाता / गोंदिया
जिले की अनेक शाला, ट्यूशन कक्षा व हॉस्पिटल में लगनेवाली आग से सर्वसामान्य को नाहक जान गंवानी पड़ती है। जिले की अनेक शालाओं में अग्निशमन यंत्र ही नहीं हैं। जिले की जिप की 1653 शालाओं में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी जान खतरे में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

जिप शालाओं में अग्निशमन यंत्र नहीं होने की बात सामने आई है। जबकि कुछ शालाओं में यह यंत्र है। लेकिन उन शालाओं के अग्निशमन यंत्रों की अवधि समाप्त हो गई है। उन्हें बदलने के लिए दो से तीन हजार रु. खर्च आता है। जिससे किसी भी शाला ने यह नहीं किया। इसमें जिप शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कितना सजग है यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

गराड़ा की जिला परिषद स्कूल में हरित अभियान, 90 पौधों का रोपण

संवाददाता / तिरोड़ा
पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीन फाउंडेशन तिरोड़ा द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के अंतर्गत अभियान के 810वें दिन गराड़ा स्थित जिला परिषद स्कूल परिसर में 90 पौधों का रोपण किया गया। यह पौधारोपण 'हरित स्कूल' संकल्पना के तहत गराड़ा के उपसरपंच व्यंकट रेवतकर के अनुरोध पर किया गया। इस अवसर पर सरपंच, उपसरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्रामवासी तथा ग्रीन फाउंडेशन तिरोड़ा की टीम ने सहभागिता की।

विद्यालय परिसर में आम, जामुन, नीम, बकुल, अमलतास, बादाम, बेहड़ा, चंपा और बेल सहित विभिन्न प्रजातियों के कुल 90 पौधे लगाए गए। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा विद्यालय परिसर को हराभरा और सुंदर बनाना है। ग्रीन फाउंडेशन तिरोड़ा द्वारा लगातार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक कुल 3,121 पौधों का रोपण किया जा चुका है। संस्था की टीम ने पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर



उपस्थित ग्रामवासियों ने ग्रीन फाउंडेशन तिरोड़ा के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की सराहना करते हुए पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहयोग करने का आश्वासन दिया।

भाईचारे से मनाया भुजलिया पर्व

तिरोड़ा : रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाए जाने वाले पारंपरिक भुजलिया पर्व को बिरसीफाटा, लाखेगांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह और सद्भावना के वातावरण में मनाया गया। पर्व के अवसर पर महिलाओं और बच्चों ने भुजलियों की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद शाम के समय भुजलियों का विधि-विधान से विसर्जन किया गया। भुजलिया पर्व की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। महिलाओं द्वारा भुजलिया तैयार करने के बाद रक्षाबंधन के दूसरे दिन उन्हें पूजा के लिए सजाया गया।

स्वास्थ्य सूचकांक में गोंदिया राज्य में अक्ल



संवाददाता / गोंदिया
जिला स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पहली तिमाही के स्वास्थ्य सूचकांक रैंकिंग में गोंदिया जिले ने 46.57 अंक प्राप्त कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए शनिवार को पुणे में आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सेवा

DHO रैंकिंग में 46.57 अंक के साथ पहला स्थान, विभाग को प्रोत्साहन

निःशुल्क जांचों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। सुरक्षित प्रसूति, प्रसूति पूर्व व

दवाखाना तथा 17 नागरी स्वास्थ्य वर्धनी उपकेंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मातृ व शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, विभिन्न टीकाकरण, आरसीएच ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन, क्षय रोग नियंत्रण तथा आयुष्मान के तहत विभिन्न

आयुक्त व राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अभियान संचालक संजय काटकर (भाप्रसे) के हाथों जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अभिजीत गोल्हार को सम्मानित किया गया।

राज्य स्तर पर प्रत्येक तीन माह में जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला शल्य चिकित्सक द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निर्धारित उद्देश्यों और सूचकांकों की पूर्ति के आधार पर जिलों का मूल्यांकन किया जाता है। इसी मूल्यांकन में गोंदिया ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया है। रैंकिंग में नागपुर 45.79 अंक के साथ दूसरे, वर्धा 45.17 अंक के साथ तीसरे, अकोला 44.39 अंक के साथ चौथे और गडचिरोली 44.14 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रहा। जिले में 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक नागरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 263 स्वास्थ्य उपकेंद्र, चार आपला

पश्चात फॉलोअप, 108 व 102 एंबुलेंस सेवा तथा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी योजनाओं पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जिला स्तरीय समन्वय समिति जिलाधीश मंदार पक्की और मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ दोंतुला के मार्गदर्शन में कार्यरत है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अभिजीत गोल्हार ने कहा कि यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। तहसील स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का प्रत्यक्ष निरीक्षण, ऑनलाइन बैठकें तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों की लगातार समीक्षा के कारण विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार हुआ है।

नदीटोला- भजेपार संकरी सड़क पर मौत का जाल

सड़क की माप व चौड़ीकरण की ग्रामीणों की मांग



संवाददाता / सालेकसा

तहसील में नदीटोला से भजेपार के बीच की मुख्य सड़क बेहद संकरी हो जाने से वाहन चालकों व यात्रियों की जान को खतरा पैदा हो गया है। अपर्याप्त चौड़ाई, सड़क के दोनों ओर बढ़ी घनी झाड़ियां और बारिश के मौसम में होने वाली कीचड़ के कारण इस मार्ग पर बड़ा हादसा होने की तीव्र संभावना पैदा हो गई

है।

यह मार्ग नदीटोला, भजेपार और बोदलबोडी क्षेत्र के नागरिकों, किसानों व विद्यार्थियों के लिए रोजमर्रा के आवागमन का मुख्य आधार है। लेकिन, सड़क संकरी होने के कारण सामने से दूसरा वाहन आने पर रास्ता देना मुश्किल होता है। कई बार वाहनों को सड़क से नीचे उतारना पड़ता है, जिससे दोपहिया वाहन

चालकों का नियंत्रण छूटकर दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही, सड़क के किनारे बढ़ी झाड़ियों के कारण मोड़ पर सामने से आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता, जिससे रात के समय यात्रा करना और भी खतरनाक हो जाता है। इसलिए सड़क के दोनों ओर की झाड़ियां-झाड़संखाड़ तुरंत साफ की जाएं, सड़क की बदहाली दूर कर उसका तत्काल चौड़ीकरण किया जाए, खतरनाक मोड़ों पर आवश्यक सूचना फलक लगाए जाएं, कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले संबंधित विभाग व जनप्रतिनिधि इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देकर ठोस उपाययोजना करें, ऐसी मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है।

विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को 'जिला गौरव' पुरस्कारों से किया जाएगा सम्मानित

संवाददाता / गोंदिया
पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्वास, सत्य और एकजुटता का प्रतीक बने प्रेस ट्रस्ट ऑफ गोंदिया की स्थापना के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में संस्था का 11वां स्थापना दिवस एवं भव्य सत्कार समारोह मंगलवार, 01 सितंबर को शाम 6:00 बजे होटल जिंजर (द गेटवे) में आयोजित किया गया है।

कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा सांसद राजेंद्र जैन द्वारा किया जाएगा, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेस ट्रस्ट ऑफ गोंदिया के अध्यक्ष अपूर्व मेठी करेंगे। इस समारोह में मुख्य अतिथि के

रूप में विधान परिषद सदस्य व पूर्व मंत्री डॉ. परिणय फुके, विधायक विनोद अग्रवाल, विधायक राजकुमार बडोले, विधायक विजय रहांगडाले, जिला परिषद अध्यक्ष लायकराम भंडारकर और नगराध्यक्ष सचिन शेंडे उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही विशेष अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे और अपर जिलाधिकारी अभिजीत घोरपडे की प्रमुख उपस्थिति रहेगी।

इस गरिमामय समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले गणमान्य व्यक्तियों का विशेष सम्मान किया जाएगा। इसमें वरिष्ठ पत्रकार

भगत ठकरानी को 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ गोंदिया जीवन गौरव सम्मान 2026-27' प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही दुर्लिचंद बुढे को स्व. श्री रणजीतभाई जसानी स्मृति सामाजिक सेवा सम्मान, अनिल निलोजन अधिकारी डॉ. रूपेशकुमार राऊत को स्व. श्री रामकिशोरजी कटकवार स्मृति कर्तव्यनिष्ठ सम्मान, प्रा. सत्यनारायण यदुवंशी को स्व. श्री रामदेवजी जायसवाल स्मृति साहित्यरत्न सम्मान, दादा फुडे को स्व. श्री मोहनलालजी चांडक स्मृति कृषिरत्न सम्मान, नरेंद्र गौतम को

सहयोग संस्थान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान, दिव्या नितिन भोजवानी को स्व. श्री दीपम देवेद्रभाई पटेल स्मृति योगरत्न सम्मान, डॉ. सुधीर जोशी को स्व. प्राचार्य श्री योगेश नासरे स्मृति विशेष सेवा सम्मान और वृक्षधारा फाउंडेशन को स्व. श्री रूपनारायण झा स्मृति विशेष सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

इस गौरव समारोह में जिले के पत्रकारों, नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील उपाध्यक्ष जयंत शुक्ला, संतोष शर्मा, सचिव रवि



प्रेस ट्रस्ट ऑफ गोंदिया
नौदणी क्रमांक : ई-९४ (गोंदिया)



आर्य, कोषाध्यक्ष हिदायत शेख सहित कार्यकारिणी सदस्य अंकुश गुंडावार, कपिल केकत, हरिंद्र मेठी, आशीष

वर्मा, जाहिर खान, मुकेश शर्मा, राजन चौबे, नरेश रहिले, रवींद्र तुरकर, संजीव बापट, राहुल जोशी, मनोज

ताजणे, योगेश राऊत एवं समस्त प्रेस ट्रस्ट ऑफ गोंदिया परिवार की ओर से की गई है।



संपादकीय

डिजिटल उलझन

भारत में लंबे समय से अभिभावक, शोध निष्कर्ष और मीडिया बता रहा था कि बच्चों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का घातक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हमारे नीति-नियंता इस तरह के मामलों में तब ध्यान देते हैं जब इस बाबत निष्कर्ष पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका से आए। फेसबुक और इंस्टाग्राम से बच्चों को हुए नुकसान को लेकर पिछले दिनों अमेरिका की अदालतों में वाद दायर किए गए। इस बाबत किए गए दावों के बाद मेटा को १८ अरब डॉलर तक भुगतान करने का फैसला अदालतों ने दिया। इस जुर्माने से इस बात को भी मान्यता मिली है कि नुकसान सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल के तरीके से ही नहीं होता, बल्कि उसके डिजाइन से भी हो सकता है। आरोप लग थे कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चों को इसकी लत लग जाती है। दरअसल, यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है कि किस तरह बच्चों को उपभोक्ता में तब्दील किया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि माता-पिता स्क्रीन टाइम को तो सीमित कर सकते हैं, लेकिन वे उन एल्गोरिदम को नहीं देख सकते हैं, जो यह तय करते हैं कि उन घंटों के दौरान बच्चा क्या देखता है। दरअसल, इन प्लेटफॉर्म द्वारा बड़ी ही चालकी से इनफिनेट स्क्रॉलिंग, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, नोटिफिकेशन, लाइक्स और दूसरे एंगेजमेंट टूल इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे बच्चों का बार-बार ध्यान खींचें और उन्हें छोटी स्क्रीन पर वापस लाएं।

दरअसल, अभिभावकों ने अमेरिकी अदालत में कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि बच्चे अधिक समय तक ऑनलाइन रहते हैं, बल्कि यह है कि प्लेटफॉर्म को बच्चों को लत लगाने के लिये डिजाइन किया गया है। मेटा ने कुछ सुरक्षा उपायों को लेकर प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें रोजाना की सीमाएं, रात के समय की पाबंदियां तथा लगातार बढ़ावा देने वाले फीचर्स में बदलाव शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद कंपनी का विज्ञापन आधारित बिजनेस मॉडल काफी हद तक वैसा ही बना रहेगा। इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ी है कि जब तक कंपनी का व्यावसायिक मॉडल नहीं बदलेगा, सकारात्मक नतीजों की उम्मीद बेमानी होगी। अमेरिका में अभिभावकों की जीत के बाद भारत को सबक लेते हुए जल्दबाजी में इस पर पूरी तरह बैन लगाने से बचना चाहिए। सारी जिम्मेदारी अभिभावकों की भी न हो। इसके लिये जो डिजिटल नियम बनें, उनमें प्लेटफॉर्म्स को प्रोडक्ट डिजाइन से होने वाले संभावित नुकसान हेतु जवाबदेह बनाना चाहिए। साथ ही बच्चों को लक्षित करने वाले व्यवहार संबंधी विज्ञापनों पर सख्त रोक लगानी चाहिए। बच्चों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले रिकमेंडेशन सिस्टम का स्वतंत्र ऑडिट हो। वहीं उम्र की पुष्टि करने वाले सिस्टम को बच्चों की निजी जानकारी का ऐसा डेटाबेस नहीं बनाना चाहिए, जो उनकी निजता में हस्तक्षेप कर सके। फोन में सेफ्टी सेटिंग्स हमेशा विद्यमान रहनी चाहिए, ताकि मां-बाप को माथापच्ची करके उसे ढूँढ कर चालू न करना पड़े। निस्संदेह, जिन प्लेटफॉर्म्स के पास बच्चों को लत लगाने की तकनीक है, उनके पास ही नुकसान को कम करने की तकनीक भी है। अतः जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की हो।

नेपाल बाढ़ : स्टेशन पहुंचते ही परिजनों में दिखी खुशी की लहर

नागपुर : नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण काठमांडू में फंसे नागपुर और विदर्भ के १०२ श्रद्धालुओं की आखिरकार सकुशल घर वापसी हो गई. रविवार तड़के ४.३० बजे सभी श्रद्धालु नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे. उनके पहुंचते ही पिछले कुछ दिनों से चिंता में डूबे परिजनों ने राहत की सांस ली. नागपुर सहित विदर्भ के १०६ श्रद्धालुओं का समूह १९ अगस्त को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर सहित विभिन्न तीर्थस्थलों के दर्शन के लिए रवाना हुआ था. २१ अगस्त को उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए. तीर्थयात्रा पूरी कर यह समूह २५ अगस्त को काठमांडू लौटा. इसी दौरान नेपाल में बाढ़ के कारण बने भीषण हालात से देश से बाहर निकलने के रास्ते बाधित हो



गए और श्रद्धालु काठमांडू में ही फंस गए.

इस बीच बुधवार को रसुवा सहित मध्य नेपाल के अन्य क्षेत्रों में आई फ्लैश फ्लड से बड़ी जनहानि हुई. कई बस्तियां, सड़कें, पुल और जलविद्युत परियोजनाएं बह गईं. करीब २४०० से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं. रविवार तड़के नागपुर पहुंचे श्रद्धालु बाढ़

प्रभावित नेपाल-तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते बंद होने के कारण उन्हें काठमांडू में ही रुकना पड़ा. २७ अगस्त की रात उन्होंने काठमांडू छोड़ा. काठमांडू से जनकपुर, बिहार पहुंचने के बाद बस से वे दानापुर आए. इसके बाद २८ अगस्त को पटना से ट्रेन द्वारा नागपुर के

अनुदानित स्कूलों में ८ ० प्रतिशत रिक्त पद भरने का रास्ता साफ

गडचिरोली : राज्य की निजी अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है.

राज्य सरकार ने कनिष्ठ लिपिक, पूर्णकालिक ग्रंथपाल और प्रयोगशाला सहायक इन तीन संगर्गों के ८० प्रतिशत रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी है. इससे शिक्षित बेरोजगार

युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर उपलब्ध होगा. शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियमित भर्ती लंबे समय से रुकी हुई थी. करीब १४ वर्षों बाद सरकार ने भर्ती को मंजूरी दी है.

राज्य में लिपिक एवं प्रयोगशाला सहायकों के करीब ३० हजार स्वीकृत पद हैं, जिनमें से २३ हजार से अधिक पदों पर भर्ती होने की संभावना है.

गडचिरोली जिले में शिक्षकेत्तर

कर्मचारियों के १,२४३ पद रिक्त बताए जा रहे हैं. ऐसे में जिले के पात्र उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

रिक्त पदों में नियम अनुसार पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों की प्रक्रिया पहले पूरी की जाएगी. इसके बाद शेष पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा. नियुक्ति प्रक्रिया में पदों की मंजूरी, आरक्षण, रोस्टर और

अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए जाएंगे. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शासन के मौजूदा नियमों के अनुसार शुरूआती तीन वर्षों तक मानधन पर हो सकती है. प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर ज्ञान, अनुभव और आयु सीमा संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित होंगी.

रिक्त भूखंड नए उद्योजकों को तत्काल उपलब्ध कराएं

वर्धा : जिले के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एमआईडीसी में उपलब्ध भूखंडों का प्रभावी उपयोग किया जाए. भूखंड लेने के बावजूद उद्योग शुरू न करने वाले उद्यमियों की विस्तृत समीक्षा करके भूखंडधारकों का ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकरण किया जाए. जिन भूखंडों पर उद्योग शुरू हैं, उन्हें 'ए', उद्योग शुरू करने के बाद वर्तमान में बंद इकाइयों को 'बी' तथा भूखंड लेने के बावजूद अब तक उद्योग शुरू नहीं करने वालों को 'सी' श्रेणी में शामिल कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए. साथ ही एमआईडीसी के खाली भूखंड नए उद्यमियों को उपलब्ध कराने के निर्देश उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने दिए.

जिलाधिकारी कार्यालय में पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर की उपस्थिति में उद्योग, एमआईडीसी और



सीएमईजीपी योजना की समीक्षा बैठक उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने ली. इस अवसर पर जिलाधिकारी वामनती सी, एमआईडीसी संगठन के अध्यक्ष प्रवीण हिवरे, नागपुर विभाग के उद्योग एवं सेवा सह आयुक्त शिवकुमार मुद्गमवार तथा जिला उद्योग केंद्र के उद्योग एवं सेवा सहायक आयुक्त सुनील हजारे उपस्थित थे.

भूदान की जमीन का पट्टा नहीं मिल रहा

कारंजा घाटगे : भूदान

आंदोलन के तहत दान में दी गई जमीन का पट्टा अब तक नहीं मिलने से वारिसों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है. सातबारा में एक नाम के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से अन्य वारिस इन योजनाओं से वंचित हो रहे हैं. भविष्य में जमीन को लेकर परिवार में विवाद न हो, इसके लिए वारिस पट्टा प्राप्त करने के लिए लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं. आचार्य विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ आंदोलन की शुरुआत पवनार से की थी. उनके आह्वान पर उस समय अनेक लोगों ने अपनी जमीन दान की थी. वर्तमान में इस कार्य की देखरेख 'भूदान यज्ञ मंडल' द्वारा की जाती है. संबंधित कार्यालय यवतमाल में होने के कारण वर्धा जिले से जुड़े भूदान जमीन के मामलों में नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

आचार्य विनोबा भावे के आह्वान पर मदनी निवासी बापूराव भुयार ने मौजा मदनी स्थित सर्वे नंबर 95 की 2.40 अरब कृषि भूमि भोगवटादार वर्ग-2 के तहत



गंगाराम राऊत को दान दी थी. गंगाराम राऊत के निधन के बाद उनकी पत्नी गुणाबाई राऊत और छोटे बेटे ज्ञानेश्वर राऊत का भी निधन हो गया. वर्तमान में लक्ष्मण राऊत, बाबाराव राऊत, बेटी गीता तथा मृत ज्ञानेश्वर राऊत के वारिसों के नाम सातबारा पर दर्ज हैं. नियमानुसार जमीन का बंटवारा-पत्र भी संभव नहीं है. सभी वारिसों को योजनाओं का लाभ मिले और भविष्य में विवाद न हो, इसलिए लक्ष्मणराव और बाबाराव राऊत पट्टा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. इस समस्या को लेकर 9 जुलाई को विधायक सुमित वानखेड़े के माध्यम से महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के पास शिकायत दर्ज कराई गई.

बाघ के पंजे, सुअर के दांत और हिरण की खाल बरामद

चंद्रपुर : पत्नी को धमकी देने वाला पति खुद ही पुलिस के जाल में फंस गया. पति से परेशान पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति उसे तंग करता है. साथ ही वन्यजीव के अंगों की तस्करी करता है. इसके बाद दी गई तलाशी तथा जांच अभियान में पुलिस ने बाघ के पंजे, सुअर के दांत और हिरण की खाल बरामद की. आरोपी पति विक्की दुसाने को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने वन्यजीव तस्करी का मामला जांच के लिए चंद्रपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी घनश्याम नायगमकर को सौंप दिया है. 26 अगस्त को घरेलू उत्पीड़न से तंग आकर पीड़ित महिला ने

पत्नी ने सौंपे जंगली जानवरों के अंग

शिकायत दर्ज कराते समय पीड़िता ने आरोपी पति द्वारा जमा करके रखे गए कुछ जंगली जानवरों के अंग पुलिस को सौंप दिए. इनमें बाघ के पंजे, सुअर, हिरण का मांस और दो अन्य जंगली जानवर शामिल थे. रामनगर पुलिस ने तुरंत आपराधिक कानून के तहत मामला दर्ज किया. वन विभाग ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक अलग मामला दर्ज किया है.



रामनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि उसका पति विक्की लगातार उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, पीटता है.

शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति घर में रखे जंगली जानवरों के अंगों को दिखाकर उसे गंभीर धमकियां भी देता था और कहता था, 'मैं तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दूंगा.' घटना की गहन जांच के बाद रामनगर पुलिस निरीक्षक प्रभावती एक्करे के ने आरोपी विक्की दुसाने को गिरफ्तार कर चंद्रपुर वन विभाग को सौंप दिया है.

पुलिस और वन विभाग संयुक्त रूप से इस मामले में जांच कर रहे हैं कि क्या इस मामले में वन्यजीवों के अंगों की अवैध खरीद-बिक्री या तस्करी में कोई और भी शामिल है.

7 दशक बाद भी पुल की मरम्मत नहीं

संवाददाता । सेलू

सेलू और कारंजा तहसील को जोड़ने वाले हिंगणी गांव के पास स्थित बोर नदी के पुल की हालत बेहद खराब हो गई है. पुल पर जगह-जगह पड़े जानलेवा गड्ढे और बारिश के कारण जमा हुई चिकनी मिट्टी की परत से वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है.

करीब सात दशक पहले बनाया गया यह पुल इस क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण आवागमन मार्ग है. यह पुल सेलू तहसील के प्रमुख बाजार हिगणी को कारंजा तहसील और मालेगांव से जोड़ता है. नानबर्डी, डोंगरगांव, वाडी, खैरी मेनखात मार्ग से सेलू तथा झड़सी, क्षीरसमुद्रपुर, अंतरंगाम मार्ग से आजी, धामणगांव, सालई, सोंडी, आमगांव, मालेगांव ठेका और कारंजा (घाडगे) की ओर जाने वाला यातायात इसी पुल से होकर गुजरता है. इस मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों नागरिकों, स्कूली विद्यार्थियों और वाहनों की भारी आवाजाही रहती है. पुल पर पड़े गड्ढे बेहद गहरे और खतरनाक हो



गए हैं. संबंधितों द्वारा मरम्मत की ओर लगातार की जा रही अनदेखी के कारण वाहन चालकों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है.

रात के समय इस क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था नहीं होने से अंधेरे में ये गड्ढे दिखाई नहीं देते. इसके कारण यहां छोटी-मोटी दुर्घटनाएं रोज की बात हो गई हैं. भविष्य में कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है और जान-माल के नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हाल ही में हुई हल्की बारिश के कारण पुल पर चिकनी मिट्टी की परत जम गई है, जिससे

दोपहिया वाहन फिसलने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है.

करीब 7 दशक पुराने इस पुल का संबंधित प्रशासन तत्काल निरीक्षण करे. नया पुल बनाना संभव न हो तो कम से कम पुल पर पड़े गहरे गड्ढों को भरकर उचित मरम्मत की जाए, ऐसी पुर्जोर मांग क्षेत्र के ग्रामीणों की ओर से की जा रही है. कोई बड़ा हादसा होने से पहले प्रशासन गंभीरता से ध्यान देकर तत्काल उपाययोजना करे, आज्ञादी के दशकों बाद भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. वहीं विकास केवल शहरों का हो रहा है.

जिला योजना निधि में सांसदों को १ ० % कोटा

चंद्रपुर : लोकसभा क्षेत्र के अत्यधिक विस्तार और तुलनात्मक रूप से सांसदों को मिलने वाले अपर्याप्त फंड के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में बाधा आ रही है. इसे ध्यान में रखते हुए, सांसद छत्रपति शाहू महाराज के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी के सात सांसद प्रतिभा धानोरकर ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की.

उन्होंने जिला योजना निधि में सांसद के लिए 10 प्रतिशत कोटा की मांग की. वर्तमान में, सांसद निधि के तहत सालाना केवल 5 करोड़ रु. उपलब्ध हैं, जो एक बड़े निर्वाचन क्षेत्र में सैकड़ों गांवों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहद अपर्याप्त है. इससे स्थानीय स्तर पर सड़कों, बुनियादी ढांचे और अन्य नागरिक कार्यों को पूरा करने में बड़ी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, और

सांसद प्रतिभा धानोरकर ने बताया कि राज्य सरकार को अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन प्रतिनिधियों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है.

इस समस्या के समाधान के रूप में सांसदों ने मुख्यमंत्री के समक्ष 5 प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें से मुख्य मांग यह है कि जिले के जिला योजना विकास निधि के वार्षिक बजट का 10 प्रतिशत सांसदों की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाए. सांसदों की सिफारिशों के अनुसार राज्य के बजट से लोक निर्माण विभाग, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और केंद्रीय सड़क निधि के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम दो सड़कों और विकास कार्यों को मंजूरी देने तथा परंपरा के अनुसार बजट सत्र से पहले सभी सांसदों की बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया.

नियम सख्त, पर शहर में खुले आम उल्लंघन!

50% सूखे और गीले कचरे का वर्गीकरण नहीं हो रहा

नागपुर : सूखा और गीला कचरा जगह पर ही वर्गीकृत करने, सेनेटरी पैड सहित घातक कचरे को सामान्य कचरे से अलग करने सहित कई नए दिशा निर्देश केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया है. इसके अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 आगामी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं. लेकिन नागपुर शहर में रोजाना इकट्ठा होने वाला 1400 मीट्रिक टन कचरे में से आधा अर्थात 50 फीसदी मिश्रित कचरा भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में पहुंच रहा है.

नियमों का कड़ाई से पालन नहीं होने के लिए सीधे तौर पर कचरा कंपनी एजी एन्वायरो (एथोनी वेस्ट हैंडलिंग) जिम्मेदार है. करार के तहत उन्हें शत प्रतिशत



वर्गीकृत कचरा भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में पहुंचाना आवश्यक है. लेकिन दोनों ही कंपनियां यह नहीं कर पा रही हैं. दलील यह भी दी जा रही है कि कचरे की प्रक्रिया करने वाली कंपनी भूमि ग्रीन व सुसबिडी मिक्स कचरे को स्वीकार रही है. ऐसे में केंद्र सरकार ने तो नियम बना दिया, लेकिन

उसके कड़ाई से पालन कराने में मनपा ही पहुंचाना आवश्यक है. अप्रैल महीने से ही नए नियम लागू हो चुके हैं. इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नागपुर महानगरपालिका ने नागरिकों, व्यापारियों, संस्थानों, गृह निर्माण संस्थाओं तथा बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न करने वाले

प्रतिष्ठानों से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है. इसे लेकर मनपा की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक नागरिक और संस्था की जिम्मेदारी है कि गीले और सूखे कचरे सहित निर्धारित श्रेणियों में कचरे का सोत पर ही वर्गीकरण किया जाए. नियमों के अनुसार कचरे का पृथक्करण नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

कचरा जलाने, सार्वजनिक स्थल पर फेंकने पर लगेगा भारी जुर्माना

मनपा ने नागरिकों से घर से ही कचरे का चार श्रेणियों में वर्गीकरण करने, कचरा संग्रहण कर्मचारियों को निर्धारित रद्दति से कचरा सौंपने तथा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं जलाने और फेंकने की अपील की है. अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया गया तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जा सकती है. प्लास्टिक, निर्माण सामग्री और ई-कचरे को सामान्य कचरे में नहीं मिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही कचरा सड़क अथवा नालियों में डालने के बजाय निर्धारित व्यवस्था के अनुसार देने को कहा गया है.

हर साल श्रद्धालुओं को नेपाल ले जाते हैं

श्रद्धालुओं को नेपाल तीर्थयात्रा पर ले जाने वाले पंडित श्रीधर त्रिपाठी ने बताया कि मैं हर साल श्रद्धालुओं को नेपाल की तीर्थयात्रा पर लेकर जाता हूं. इस वर्ष ११५ श्रद्धालु साथ थे. इनमें से सात लोग पहले ही भारत लौट चुके हैं. हालांकि, निर्मला पांडे (७२) को दिल का दौरा पड़ने के कारण काठमांडू के अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है. उनका बेटा नागपुर से काठमांडू पहुंच चुका है.

लिए रवाना हुए. नागपुर रेलवे स्टेशन पर भाजपा के नागपुर शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने श्रद्धालुओं का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया.

बीपी बड्वा, बिगड़ी तबीयत : नागपुर से गए श्रद्धालु २३ अगस्त को बाढ़ की चपेट में आए मुक्तिनाथ, त्रिशूली नदी और मनोकामना देवी मंदिर में दर्शन के लिए गए थे. वहां से लौटने के बाद उस क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई, जिन स्थानों पर वे दर्शन के लिए गए थे, वहां बड़े पैमाने पर जनहानि होने की

जानकारी मिलते ही श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई. कई श्रद्धालुओं का बीपी बढ़ गया और उनकी तबीयत बिगड़ गई. समूह में महिलाओं की संख्या भी काफी थी. हालांकि, किसी तरह इस संकट से निकलकर नागपुर पहुंचने की प्रतिक्रिया तिरंगा चौक निवासी रेखा कस्तुरे, शाहूनगर-मानेवाड़ा की नंदा खंते, सिंगाबाई टाकली निवासी अनिता वाकोड़े और मानेवाड़ा के शिवशक्तिनगर निवासी योगेश गावंडे ने व्यक्त की.

महावितरण ने भेजा 1 1 4 1 0 का बिजली बिल

अजब गजब : घर में है सिर्फ एक पंखा और दो बल्ब

राजुरा : तहसील के भुरकुंडा गांव में बिजली विभाग के कारभार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गांव के विट्ठल कोटरंगे, जो मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, उनके घर में महज एक पंखा और दो लाइट हैं. लेकिन महावितरण ने ११४१० रु. का भारी-भरकम बिजली बिल भेज दिया है. विट्ठल कोटरंगे खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं. इस महंगाई के दौर में दो वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे कमाना मुश्किल है.

एक माह में मेहनत कर जितना पैसा नहीं कमाते उससे ज्यादा बिजली बिल विभाग ने भेज दिया है. बिजली विभाग के कर्मचारी बार बार उनके घर आकर बिजली काटने की धमकी दे रहे हैं. अगर बिल नहीं भरा तो बिजली काट देंगे, जिससे उनके

होश उड़ गए हैं. विट्ठल कोटरंगे का कहना है कि जिनकी महीने भर की कुल कमाई ११ हजार रु. भी नहीं है, वे इतनी बड़ी रकम एक बार में कहां से भरेंगे? इतना ही नहीं, समय पर बिल न जमा करने पर बिजली कनेक्शन काटने की धमकियां दी जा रही हैं.



मैं जीने को मजबूर हूँ. नागरिकों का सीधा सवाल है कि जब गलती बिजली विभाग के कर्मचारियों की है, तो उसकी सजा आम जनता क्यों भुगतें? शासन और संबंधित विद्युत विभाग से पूरे मामले का तत्काल संज्ञान लेकर एकमुश्त भेजे गए गलत एवं अत्यधिक बिजली बिलों को शीघ्र दुरुस्त करने की मांग की गई है. नागरिकों ने चेतावनी दी है कि बिलों में सुधार नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे.

हाथियों के उत्पात जारी, किसान त्रस्त

सिर्सी से पोर्ला वनपरिक्षेत्र में आगमन, देलोडा में पैरों तले रौंदी फसलें



संवाददाता । गड़चिरोली आरमोरी तहसील के सिस्सी उपवनक्षेत्र अंतर्गत सिस्सी-गणेशपुर खेत परिसर में शुक्रवार की रात के दौरान जंगली हाथियों ने फसलों का नुकसान

कायमस्वरूपी उपाययोजना करें

बीते कुछ वर्षों से जंगली हाथियों का वितरण शुरू होने से प्रतिवर्ष हाथियों द्वारा फसलों का नुकसान किया जा रहा है. इस वर्ष प्रकृति द्वारा किसानों का साथ दे रही है, जिससे खेतों में फसलें लहलहाते नजर आ रहे हैं. लेकिन जंगली हाथियों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरती नजर आ रही है. जिससे जंगली हाथियों के चलते फसलों के नुकसान को रोकने कायमस्वरूपी उपाययोजना करने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है. फिलहाल जंगली हाथियों का झुंड देलोडा परिसर के जंगल परिसर में है. अब यह झुंड चुरचुरा बीट में प्रवेश करने की संभावना है. जिससे परिसर के किसानों की चिंता बढ़ गई है.

फसलों को रौंद दिया. और किसानों का व्यापक नुकसान किया है. जिले में बीते कुछ वर्षों से जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है. जंगली हाथियों के विचरण के चलते किसान त्रस्त हुए हैं. इस दौरान गुरूवार को आरमोरी तहसील के खेतों मेंउद्यममचाकर पैरो तले किसानों की

चौबीस घंटे में 20 मिमी बारिश दर्ज

वर्धा : लंबी प्रतीक्षा के बाद जिले में शनिवार को दिनभर झमाझम बारिश चली. पिछले चौबीस घंटे में औसतन 20 मिमी बारिश दर्ज की गई. कम अधिक मात्रा में चली बारिश से जिले के जलाशयों के जलस्तर में थोड़ी वृद्धि देखने मिली. पिछले चौबीस घंटे में जिले के वर्धा तहसील में 18.1 मिमी, सेलूम में 30.6 मिमी, देवली में 17.2 मिमी, आर्वी में 23.4 मिमी, आष्टी में 17.2 मिमी, कारंजा में 29.9 मिमी, हिंगनघाट में 9.8 मिमी तथा समुद्रपुर तहसील में 22.5 मिमी बारिश हुई है. अगस्त माह में अब तक औसतन 60.7 मिमी बारिश दर्ज की गई. पिछली तूलना में अत्यंत कम बारिश इस साल अगस्त माह में हुई है. इस वर्ष पहले ही मानसून ने देरी से जिले में दस्तक दी.

छह साल पहले सड़क चौड़ीकरण में पुराना बसस्टॉप तोड़ा

मांडगांव : समुद्रपुर तहसील के बड़े गांवों में शामिल मांडगांव में यात्रियों के लिए आज तक बसस्टॉप उपलब्ध नहीं किया गया है. बारिश के दिनों में बस का इंतजार करने वाले विद्यार्थियों, बुजुर्गों और नागरिकों को सड़क किनारे खड़े रहना पड़ता है. बारिश से बचने के लिए मजबूरी में छतरी अथवा पानचपरी का सहारा लेना पड़ता है. वर्धा जिले के अंतिम छोर पर वना नदी के किनारे बसा मांडगांव धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व

3 माह से जाफ़ाबाद की घंटागाड़ी बंद

संवाददाता । गड़चिरोली सिरोंचा तहसील के जाफ़्राबाद ग्राम पंचायत की कचरा संग्रहण घंटागाड़ी पिछले तीन महीनों से बंद पड़ी है. इसके चलते गांव में कचरा संग्रहण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर सवाल खड़ा होने के चलते भाकपा ने सरकार के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत का संज्ञान लेते हुए पंचायत समिति सिरोंचा ने 10 अगस्त को जांच समिति गठित कर प्रत्यक्ष जांच के आदेश दिए थे. जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों की ओर से जल्द ही घंटागाड़ी शुरू कर नियमित रूप से कचरा संग्रहण करने का आश्वासन दिया गया था. लेकिन इसे एक पखवाड़ा बितने के बावजूद अबतक घंटागाड़ी अब तक शुरू नहीं हुई है. जांच समिति के आदेश के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

गांव के नागरिक लगातार कचरा संग्रहण के लिए घंटागाड़ी शुरू करने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से आखिर क्या कार्रवाई की जा रही है, यह सवाल नागरिकों द्वारा उठाया जा रहा है. जांच समिति के आदेश का वास्तव में पालन हुआ है या केवल कागजी कार्रवाई तक ही मामला सीमित रहा, इसको लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी है.

देवीपुर - वडधा मार्ग की हालत खस्ता

गड़चिरोली : गड़चिरोली तहसील के देवीपुर से वडधा मार्ग पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने से नागरिकों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से उन की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता. ऐसे में इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है. जिससे इस मार्ग की मरम्मत करने की मांग हो रही है. देवीपुर से वडधा की ओर जाते समय नाले पर बना पुल कम ऊंचाई का है. बारिश के मौसम में नाले का



जलस्तर बढ़ने पर पुल के ऊपर पानी जमा हो जाता है. पानी का स्तर अधिक बढ़ने पर कुछ समय के लिए इस मार्ग पर यातायात बंद होने

गोवंश तस्करों पर कार्रवाई

32 गोवंशीय पशुओं समेत 19.60 लाख रूपयों का माल जब्त

करनेवाले हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने ठाणेगांव-आरमोरी टी-पॉइंट के पास नाकाबंदी की. कुछ देर बाद 2 पायलटिंग वाहन तथा एम. एच. 04 जीआर 0384 क्रमांक का सड़िध्द आयशर वाहन वहां पहुंचा. पुलिस ने आयशर वाहन को रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार 2 लोगों ने जंगल की ओर भागने की कोशिश की. पुलिस ने पीछा कर कुरखेडा तहसील के आंधली निवासी प्रणय समीर जांभुलकर (20) को पकड़ा. पीछा कर जंगल से दबोचे

आरोपी आयशर वाहन की तलाशी लेने पर उसमें गोवंशीय पशुओं को अत्यंत अमानवीय तरीके से दुंसकर भरा गया था. इसी दौरान पायलटिंग कर रही काले रंग की क्रेटा कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका चालक वाहन लेकर फरार हो गया. इसके पीछे आ रही सीजी 10 एएम 8415 क्रमांक के सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार को पुलिस ने रोक लिया. कार में सवार 3 लोगों ने भी जंगल की ओर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

आरोपियों की पहचान गड़चिरोली शहर के विवेकानंदनगर निवासी शहबाज सलाम शेख (31), व

नागपुर के जाफरनगर निवासी शोहेब फारुक शेख (27) व शेख आकिब नासीर शेख के रूप में हुई.

अवैध व नियमबाह्य अस्पतालों पर होगी कड़ी कार्रवाई



संवाददाता । गड़चिरोली जिले में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और कानूनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने अवैध एवं नियमबाह्य रूप से संचालित अस्पतालों और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के खिलाफ विशेष जांच मुहिम शुरू की है. जिला शल्य चिकित्सक (सीएस) के आदेश पर यह अभियान 10 अगस्त से 10 अक्टूबर 2026 तक चलाया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, मुंबई के अभियान संचालक के निर्देशों के आधार पर जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय ने जिले में विशेष जांच के आदेश जारी किए हैं. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारियों के विशेष दल गठित किए गए हैं. इन दलों द्वारा जिले के उपजिला अस्पताल,

जिलेभर में स्वास्थ्य संस्थाओं की विशेष जांच मुहिम, जिला शल्य चिकित्सक का आदेश

जांच की जाएगी. इसके अलावा बायोमैडिकल वेस्ट प्रबंधन, अग्निशमन सुरक्षा, अन्न एवं औषधि प्रशासन के लाइसेंस, अस्पताल में प्रदर्शित सेवा शुल्क, दवा भंडार, आवश्यक मनुष्यबल, चिकित्सा उपकरण तथा मरीजों के रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जाएगी.



रखने वाला गांव है. इसके बावजूद यहां यात्रियों की सुविधा के लिए साधारण यात्री निवारा तक नहीं होना ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. करीब छह वर्ष

पहले वर्धा-सेवाग्राम समुद्रपुर मार्ग का चौड़ीकरण किया गया था. इस दौरान सड़क किनारे स्थित मांडगांव का पुराना बसस्टॉप तोड़ दिया गया. सड़क का काम पूरा होने के साथ

आदिवासी विद्यार्थी व संगठना आक्रमक

५ व १४ अगस्त का जीआर रह करने की मांग, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

संवाददाता । पेरमिली महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग की ओर से जारी किया गया विवादग्रस्त सरकारी परिपत्रक (जी.आर.) तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर अहेरी में आदिवासी विद्यार्थी तथा विभिन्न सामाजिक संगठन की ओर से अप्पर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है. इस दौरान कहा कि, विगत 15 से 20 दिनों से संपूर्ण महाराष्ट्र में आदिवासी विभाग के सरकारी कार्यालय के समक्ष विद्यार्थी व विभिन्न संगठनों की ओर से आंदोलन, मोर्चे तथा प्रदर्शन शुरू हैं. सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण आंदोलन की सुध नहीं लिए जाने से



विद्यार्थियों में रोष तीव्र हो रहा है. इसी के मद्देनजर अहेरी में भी व्यापक रोष व्यक्त करते हुए सरकार का ध्यानाकर्षण करने ज्ञापन सौंपा गया.

छात्रावास शुरू करें: ज्ञापन में 5 व 14 अगस्त को आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी किया गया

विवादग्रस्त जी.आर. बिनशर्त तत्काल रद्द करें, नए शैक्षणिक सत्र अंतर्गत स्कूल, महाविद्यालय शुरू हुए हैं. लेकिन अनेक जगह छात्रावास अबतक शुरू नहीं हुए हैं. जिससे प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए तत्काल छात्रावास शुरू करें, सरकारी आश्रमस्कूल के विद्यार्थियों को

जिले के पशु संवर्धन विभाग में 50 प्रतिशत पद हैं रिक्त



गड़चिरोली : विकास की बातें, दुर्गम जिलों के लिए विशेष योजनाएं तथा प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने की घोषणाएं लगातार की जा रही हैं, लेकिन गड़चिरोली जिले में पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभाग की स्थिति बेहद चिंताजनक है. 30 जून 2025 की स्थिति के अनुसार विभाग में स्वीकृत 491 पदों में से 255 पद रिक्त हैं, जबकि केवल 236 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं जिले में 20वीं पशुगणना के अनुसार करीब 4 लाख 58 हजार 984 पशुधन है. ऐसे में स्वीकृत पदों में से लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त होने के कारण उपलब्ध कर्मचारियों पर पशुधन की देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी है. किसानों के पशुधन की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए सरकार ने पशुसंवर्धन विभाग का गठन किया है. विभाग में पशुधन विकास अधिकारी, सहायक पशुधन विकास अधिकारी, सहायक आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, परिचर और सफाईकर्मी सहित कई महत्वपूर्ण पद स्वीकृत किए गए हैं. जिले में कुल 491 पदों को मंजूरी प्राप्त है, लेकिन इनमें से केवल 236 अधिकारी तथा कर्मचारी ही सेवाएं दे रहे हैं. बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों का खतरा बारिश के मौसम में पशुओं में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे समय में विभाग में पर्याप्त मनुष्यबल का अभाव गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है. सीमित कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यभार संभालते हुए दुर्गम एवं दूरदराज के गांवों तक पहुंचकर किसानों और पशुपालकों को सेवाएं देनी पड़ रही हैं. जिले में 2 लाख 44 हजार 439 गाय, बैल और भैंस हैं। वहीं बकरियों में भेड़ों की संख्या करीब 1 लाख 94 हजार 717, अन्य पशुओं की संख्या 10 हजार 800 तथा मुर्गियों की संख्या करीब 1 लाख 16 हजार हैं.

जनप्रतिनिधियों के बच्चे निजी स्कूलों में, फिर सरकारी स्कूलों पर भरोसा कौन करे?

करोड़ों का खर्च, कागजों पर विकास और जमीन पर घटती विद्यार्थी संख्या: जिला परिषद स्कूलों की व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल



संवाददाता । सुबोध बैस
सरकारी स्कूलों के विकास पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। कहीं डिजिटल कक्षाओं की घोषणा होती है, कहीं कंप्यूटर और खेल सुविधाओं का दावा किया जाता है तो कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन इन तमाम दावों के बीच ग्रामीण क्षेत्र की जिला परिषद स्कूलों की वास्तविक स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन जिला परिषद स्कूलों की व्यवस्था और विकास की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों के कंधों पर है, क्या उनके अपने बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? यदि सरकारी शिक्षा व्यवस्था वास्तव में गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद है, तो फिर जनप्रतिनिधियों सहित सक्षम

परिवार अपने बच्चों के लिए निजी स्कूलों को प्राथमिकता क्यों देते हैं? यह किसी के व्यक्तिगत निर्णय पर सवाल उठाने का विषय नहीं है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था पर विश्वास और

अब जनप्रतिनिधियों को देना होगा जवाब जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय जनता के बीच जाने वाले प्रतिनिधि नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग हैं। शिक्षा जैसे मूलभूत विषय पर उनकी सक्रिय भूमिका दिखाई देना आवश्यक है। यदि जनप्रतिनिधि नियमित रूप से स्कूलों का दौरा करें, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करें, विद्यार्थियों की समस्याएं समझें और शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा करें, तो सरकारी स्कूलों में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में विश्वास पैदा करने के लिए घोषणाओं से ज्यादा जरूरी है—जवाबदेही, नियमित निगरानी और जमीन पर दिखाई देने वाला काम।

जवाबदेही का सवाल जरूर है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए जिला परिषद स्कूल आज भी

आज के पांच बड़े सवाल

- जिला परिषद सदस्यों के कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं?
- करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद विद्यार्थी संख्या क्यों घट रही है?
- शिक्षकों के रिक्त पद वर्षों से क्यों नहीं भरे जा रहे?
- डिजिटल शिक्षा की सुविधाएं वास्तव में कितने स्कूलों तक पहुंची हैं?
- सरकारी स्कूलों पर विश्वास बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि स्वयं क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं?

बदलाव के लिए पांच ठोस कदम

- प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के स्कूलों का नियमित निरीक्षण करे।
- शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए।
- शिक्षकों के सभी रिक्त पद तत्काल भरे जाएं।
- अंग्रेजी, कंप्यूटर और कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत किया जाए।
- अभिभावक, शिक्षक और ग्रामवासियों की भागीदारी से स्कूल विकास योजना बनाई जाए।

निधि बढ़ी, फिर विद्यार्थी क्यों घटे ?

सरकार की ओर से स्कूलों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार निधि उपलब्ध कराई जाती है। भवन मरम्मत से लेकर डिजिटल शिक्षा और पोषण आहार तक अनेक योजनाएं चल रही हैं। इसके बावजूद कई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है। सवाल यह है कि यदि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी अभिभावकों का विश्वास सरकारी स्कूलों की ओर नहीं लौट रहा, तो समस्या आखिर कहाँ है? केवल निधि खर्च करना पर्याप्त नहीं है। उस निधि का सही उपयोग, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं का नियमित मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक है।

लगातार घटती विद्यार्थी संख्या चिंता का विषय है। सरकारी स्कूल कमजोर नहीं, व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत

कृछ अच्छा नहीं हो रहा। अनेक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति, विज्ञान, खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। कई शिक्षक अपने नवाचार और

मेहनत से विद्यार्थियों के भविष्य को दिशा दे रहे हैं। इसलिए सवाल सरकारी स्कूलों की क्षमता का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की प्राथमिकता, निगरानी और जवाबदेही का है।

हर साल बारिश के मौसम में टूट जाता है दो गांवों के बीच संपर्क

आश्वासनों में अटका बोटें-देउटोला मार्ग निर्माण

संवाददाता / गोरेगांव
तहसील के सोनी जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाला बोटें-देउटोला मार्ग पिछले करीब 21 वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बरसात के दिनों में मार्ग पर स्थित छोटे नाले में पानी भरते ही दोनों गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। वर्षों से बनी इस गंभीर समस्या के बावजूद जिला परिषद प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण की मंजूरी की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इसका खामियाजा बोटें और देउटोला के सैकड़ों किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले इस मार्ग का खड़ीकरण करीब 21 वर्ष पूर्व किया गया था। इसके बाद सड़क की स्थिति सुधारने अथवा नियमित मरम्मत करने की दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं होने से मार्ग लगातार जर्जर होता चला गया।



वर्तमान में सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और खराब सतह के कारण वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी समस्या बरसात के दौरान सामने आती है। मार्ग पर स्थित छोटे नाले में बारिश का पानी भर जाने के कारण सड़क पर आवागमन बंद हो जाता है। परिणामस्वरूप बोटे और देउटोला दोनों गांवों का संपर्क कई दिनों तक प्रभावित रहता है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, गोरेगांव तहसील के सोनी जिला परिषद क्षेत्र में पिछले वर्षों में अनेक विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। यह क्षेत्र पूर्व

जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले का निर्वाचित क्षेत्र भी रहा है। उनके कार्यकाल में क्षेत्र की कई सड़कों का निर्माण होने की बात सामने आती है। ऐसे में ग्रामीणों का सवाल है कि जब क्षेत्र की अन्य सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई, तो बोटे-देउटोला मार्ग को लगातार नजरअंदाज क्यों किया गया? किसानों का कहना है कि इस सड़क की समस्या नई नहीं है और इसके लिए कई बार संबंधित अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से मांग की जा चुकी है।

अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाएं

सड़क अर्जुनी : जिले के रेती घाटों से अवैध रूप से रेती का उत्खनन कर पर्यावरण तथा क्षेत्रवासियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सड़क अर्जुनी तहसील अंतर्गत घाटबोरी हलदीघाट में स्थित श्री जय दुर्गा माता देवस्थान समिति द्वारा तहसीलदार से गुहार लगाई गई है की चुलबंद नदी के पत्र से अवैध रूप से रेती का उत्खनन किया जा रहा है।

जिस प्रभावी रूप से रोका जाए। इस तरह का पत्र समिति की ओर से दिया गया है। इस संदर्भ में जानकारी दी जा रही है की चुलबंद नदी के तट पर श्री जयदुर्गा माता का देवस्थान है जो घाटबोरी हलदीघाट में स्थित है। इस तीर्थ स्थल को शासन ने क श्रेणी का तीर्थ स्थल घोषित किया है। प्रति वर्ष यात्रा के दौरान तथा वर्ष भर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने यहां पहुंचते हैं लेकिन यात्रा स्थल से सटकर चुलबंद



नदी पत्र से अवैध रूप से रेती का उत्खनन किया जाता है। जिससे तीर्थ स्थल तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे अवैध रूप से परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अवैध उत्खनन पर रोक लगाएं। इस तरह की गुहार श्री जय दुर्गा माता देवस्थान समिति क ओर से तहसीलदार सड़क अर्जुनी से की गई है।

श्रीरामपुर-पोंगेझरा तक कांवड़ यात्रा

संवाददाता / गोरेगांव
श्रीरामपुर में श्रद्धा व उत्साह के साथ कांवड़ यात्रा निकाली गई। श्रीरामपुर स्थित श्रीराम मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा ठाणा चौक होते हुए प्रसिद्ध शिवधाम पोंगेझरा (हिरडामाली) पहुंची, जहां कांवड़ियों ने भागवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्रीरामपुर महिला मंडल कांवड़ यात्रा समिति के विशेष सहयोग से आयोजित इस यात्रा

में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और युवा भगवा वस्त्र धारण कर कंधों पर कांवड़ लेकर शामिल हुए। महिला मंडल की प्रमुख सदस्य सोमेश्वरी बिसेन, रत्नाबाई ठाकरे समेत अन्य पदाधिकारियों ने यात्रा व्यवस्था में भूमिका निभाई। यात्रा का आयोजन मुख्य संयोजक रेवेंद्र कुमार बिसेन, गोपीचंद ठाकरे व शामराव चव्हाण के मार्गदर्शन में किया।

दूरी केवल 10 मीटर, फिर भी लगाना पड़ रहा 10 कि.मी. का चक्कर

संवाददाता / गोंदिया
स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण कुरहाड़ी-मंगाटोला-बघोली मार्ग पर पिछले कई दिनों से पुल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। जिसके चलते आस-पास के दर्जनों गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। वर्तमान में वाहन चालकों को मात्र 10 मीटर दूरी तय करने के लिए लगभग 10 किलो मीटर का लंबा फेरा लगाना पड़ रहा है। यहां तक

कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि प्रशासन को कई बार इस विषय को लेकर शिकायत की गई है लेकिन इस ओर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। इस संदर्भ में जानकारी दी जा रही है की कुरहाड़ी जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत कुरहाड़ी मंगाटोला-मराटोला-बघोली-सिलेगांव मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य



पिछले कई माह से चल रहा है। बारिश के पूर्व इस निर्माण कार्य को पूरा करना आवश्यक था।

लेकिन संबंधित विभाग की अनदेखी और पुल निर्माण करने वाली एजेंसी की लेटलतीपी के

कारण मानसून पूर्व इस निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया जा सका। पुल का निर्माण तो हो चुका है लेकिन पुल मार्ग का कुछ हिस्से का काम चल रहा है। जिस कारण इस मार्ग का आवागमन पिछले 20 दिनों से प्रभावित हो गया है। 10 मीटर दूरी तय करने के लिए वाहन चालकों को 10 किलो मीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत आपातकालीन एम्बुलेंस एवं शालेय विद्यार्थियों को हो रही है।

संवाददाता / गोंदिया
आगामी धान खरीदी सीजन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आधारभूत धान खरीदी करने वाली संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सचिवों की संयुक्त बैठक गुरुवार, 27 अगस्त को संपन्न हुई, जिसमें धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।



जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में हुई इस बैठक में 1 सितंबर 2026 से किसानों का पंजीयन शुरू करने, किसानों के बैंक खातों की आधार सीडिंग सुनिश्चित करने, धान खरीदी केंद्रों के अध्यक्ष एवं सचिवों के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य करने तथा किसानों को धान बिक्री की राशि का भुगतान 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित करने संबंधी महत्वपूर्ण

निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी संबंधित संस्थाओं को पूर्व तैयारी पूरी करने तथा शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सूचना दी। इस बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी, फेडरेशन के जिला पणन अधिकारी, पूर्व विधायक भेरसिंग नागपुरे, टीडीसी संचालक भरत दूधनाग, आदिवासी सहकारी संस्था संगठन के जिला अध्यक्ष शंकर मड़ावी सहित जिला आपूर्ति

जान से मारने का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. जी. वाघमारे का फैसला

संवाददाता / गोंदिया
पुराने विवाद को लेकर एक युवक के सिर पर लोहे की पट्टी से वार कर उसे जान से मारने का प्रयास करने वाले आरोपी को प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. जी. वाघमारे ने यह फैसला

सुनाया है और जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़ित युवक को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं। नरेंद्र कुंभरीया तांडेकर (40) निवासी नवेगांवबांध, तहसील अर्जुनी मोरगांव, ऐसा सजा सुनाए गए आरोपी का नाम है। विस्तृत जानकारी यह है कि, यह घटना 29 जून 2016 को नवेगांवबांध के टी-पाइंट परिसर में

हुई थी। शिकायतकर्ता हेमकृष्ण सूरजजोशी अपने मालिक के बेटे उमेश माधवराव आगाशे (22) के साथ दिनभर का काम निपटाकर टी-पाइंट पर एक टपरी में नाश्ता कर रहे थे। उसी समय आरोपी नरेंद्र तांडेकर वहां आया और उसने पुराने विवाद का गुस्सा मन में रखते हुए उमेश से बेवजह बहस करना शुरू कर दिया। कहासुनी के बाद गुस्साए



आरोपी ने पानठेले की टपरी बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाने

वाली भारी लोहे की पट्टी लाई और 'तुझे जिंदा नहीं छोड़ता' ऐसी धमकी देते हुए उमेश के सिर पर 3 से 4 बार जानलेवा वार किए। इस हमले में उमेश गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने तुरंत दौड़कर उसे ग्रामीण अस्पताल, नवेगांवबांध में उपचार के लिए भर्ती कराया। नवेगांवबांध पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर जांच पूरी करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल

किया। सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी और जिला सरकारी वकील एम. एस. चंदवानी ने मजबूत दलीलें पेश कीं। आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध करने के लिए सरकारी पक्ष ने कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज किए। प्रत्यक्षदर्शी गवाह, चिकित्सकीय रिपोर्ट और जब्त किए गए अपराध में इस्तेमाल हथियार, इन सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। इस बीच

प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. जी. वाघमारे ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 महीने का सश्रम कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 महीने का सश्रम कारावास, आरोपी

से वसूल की जाने वाली 25 हजार रुपये जुर्माने की राशि में से 20 हजार घायल उमेश आगाशे को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के निर्देश न्यायालय ने दिए हैं। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे और उपविभागीय पुलिस अधिकारी अजित पाटील के मार्गदर्शन में नवेगांवबांध पुलिस थाने के पैरवी अमलदार पुलिस नाईक उत्तम शोभेलाल मेहर ने उत्कृष्ट कार्य किया।

आमगांव में अतिक्रमण से बढ़ा हादसों का ग्राफ



संवाददाता / आमगांव
शहर में लगातार बढ़ता अतिक्रमण अब आम नागरिकों के लिए मुसीबत के साथ ही हादसों का कारण बनता जा रहा है। शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों के साथ ही रिसामा से आंबेडकर चौक, गांधी चौक होते हुए कामठा चौक तक फुटपाथ लगभग गायब हो चुके हैं। ऐसे में पैदल यात्रियों को मजबूरन मुख्य सड़क पर चलना पड़ रहा है।

इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। आए दिन होने वाले हादसों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आंबेडकर चौक, जगनाड़े चौक, मानकर चौक, गांधी चौक से कामठा चौक तथा कामठा चौक से मुख्य बस स्टैंड तक अतिक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई दुकानदारों ने दुकानों का सामान फुटपाथ से आगे बढ़ाकर सड़क तक फैला दिया है। इसके चलते वाहनों के आवागमन के लिए सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। सड़कों के दोनों ओर होने वाली अवैध पार्किंग और जगह-जगह लगे ठेले-खोमचे भी यातायात व्यवस्था में बाधा बन रहे हैं। फुटपाथ पर कब्जे के कारण पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है। उन्हें वाहनों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि संबंधित विभागों की उदासीनता के कारण शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। मुख्य मार्गों पर लगातार बढ़ते अतिक्रमण से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर व्यस्त समय में स्थिति और गंभीर हो जाती है तथा कई स्थानों पर जाम की समस्या उत्पन्न होती है।

मायके जाने वाली महिलाओं की भीड़ से बस अड्डे गुलजार

संवाददाता / गोंदिया
भाई-बहन के पवित्र और अटूट स्नेह का पर्व 'रक्षाबंधन' पूरे भंडारा जिले में अत्यंत उत्साह और भावपूर्ण वातावरण में मनाया गया। भोर से ही बहनों ने प्यारे भाई की कलाई पर राखी बांधकर आरती उतारी। वहीं भाइयों ने भी बहनों को आकर्षक उपहार देते हुए उनकी रक्षा का वचन दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर शहर के बाजारों में राखियां, मिठाई और उपहार खरीदने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी।

दूर रहने वाले भाइयों को राखी बांधने के लिए मायके और रिश्तेदारों के यहां जाने वाली महिलाओं और युवतियों के कारण गोंदिया मुख्य जिला बस अड्डे पर यात्रियों की अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली। हाथों में राखियां,

मिठाई और उपहारों के पैकेट लेकर सुबह से ही महिलाएं बस अड्डे पर पहुंच रही थीं। राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) की बसों में महिलाओं को टिकट में मिली 50 प्रतिशत छूट का लाभ रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रा करने वाली हजारों बहनों को मिला। इस आर्थिक राहत के कारण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और दूर-दराज की यात्रा करने वाली महिलाओं ने एसटी यात्रा को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी। भाई से मिलने की खुशी और यात्रा में मिली छूट के कारण महिला यात्रियों में काफी उत्साह दिखाई दिया। गोंदिया बस अड्डे से विभिन्न तहसील मुख्यालयों, ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के गांवों की ओर जाने वाली सभी बसें यात्रियों से खचाखच भरी हुई दौड़ रही थीं।